उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

1 अगस्त, 2018 • वर्ष 1, अंक 28

सात दिन – सात पृष्ठ

लखनऊ में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा अन्य मंत्रिगण

- ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा यूपी
- भारी निवेश से रोजगार की अपार संभावनायें
- प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करने वाले पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी
- स्मार्ट सिटी मिशन से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर
- बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की पूरी है तैयारी
- स्वतंत्रता दिवस पर एक दिन में होगा 5 करोड़ वृक्षों का रोपण

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा यूपी

60 हजार करोड़ से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास

पांच माह पूर्व फरवरी, 2018 में यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट–2018 का आयोजन हुआ था। उस समय प्रदेश में लगभग सवा चार लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। मात्र पांच माह के अंदर इनमें से 60 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का यह प्रयास सराहनीय होने के साथ–साथ आश्चर्यचकित करने वाला है। प्रदेश में इतना बड़ा निवेश सरकार के नेतृत्व की सफलता है। इसे ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी न कहकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी कहना ठीक होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह विचार लखनऊ में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 60 हजार करोड़ रुपए की 81 निवेश परियोजनाओं के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह एक अद्भुत और अकल्पनीय उपलब्धि है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं।

इन्टेन्ट को इन्वेस्टमेंट में बदल रही है योगी सरकार

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। कम समय में राज्य सरकार ने तेजी से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है और पुराने तौर–तरीकों को बदला है, ऐसा उत्तर प्रदेश में पहले कभी देखने को नहीं मिला। योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेशकों से संवाद बनाये रखा और 'इन्टेन्ट' को 'इन्वेस्टमेण्ट' में बदलने के लिए माहौल तैयार किया।

ऑनलाइन एम.ओ.यू. ट्रैकर हो, या क्लीयरेन्स के लिए 'निवेश मित्र' जैसा डिजिटल प्लेटफार्म, ये यू.पी. में बिजनेस के लिए बने अनुकूल वातावरण को दर्शाता है।

वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकारें जनहित में निवेशकों को प्रेरित करने से हिचकती नहीं हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य 'सबका साथ–सबका विकास' है। देश के विकास में उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। इसके चलते निवेशक यूपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार 'होलिस्टिक विजन' और 'इन्क्ल्यूसिव एक्शन' के एप्रोच पर काम कर रही है। यह मात्र शुरुआत है। उद्योगपति राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण अंग हैं और उनके संकल्प देश के करोड़ों नौजवानों के सपनों से भी जुड़े हुए हैं।

–नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री

"इतना बड़ा निवेश एक साथ हासिल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम ने इस काम को बहुत कम समय में अन्जाम दिया, जो अविश्वसनीय है। इतने कम समय में इतना बड़ा पूंजी निवेश अद्भुत सफलता है।

–नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

दो लाख से अधिक लोगों को सीधे मिलेगा रोजगार

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में जितना निवेश आया है उससे दो लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होगा।

उत्तर प्रदेश जिस तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उससे इसे 'वन ट्रिलियन इकोनॉमी' बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। यह प्रोजेक्ट्स डिजिटल इण्डिया और मेक इन इण्डिया को नया आयाम देने की दिशा में बहुत बड़े कदम सिद्ध होंगे।

उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही एक्सप्रेस वेज का नेटवर्क होगा। पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे के बनने के पश्चात इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। देश और प्रदेश के विकास में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है। उद्योग जगत के कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा। केन्द्र सरकार कृषि क्षेत्र में कारपोरेट इन्वेस्टमेण्ट लाने के प्रयास कर रही है। निवेश कैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे इस पर काम किया जाएगा।

भारी निवेश से रोजगार की अपार संभावनायें

- **कनोडिया ग्रुप**
  सेक्टर : सीमेंट
  निवेश : इलाहाबाद, पूर्वांचल में 1200 करोड़
  रोजगार : 800
- **फोनिक्स मिल्स**
  सेक्टर : रियल इस्टेट
  निवेश : लखनऊ में 800 करोड़ रुपये
  रोजगार : 3500

- **स्पर्श इंडस्ट्रीज**
  सेक्टर : मैन्युफैक्चरिंग
  निवेश : कानपुर देहात में 600 करोड़ रुपये
  रोजगार : 500
- **साची एजेंसीज**
  सेक्टर : सीमेंट
  निवेश : रायबरेली, इलाहाबाद में 552 करोड़
  रोजगार : 150
- **एसएलएमजी ब्रेवरेज**
  सेक्टर : फूड प्रोसेसिंग
  निवेश : लखनऊ में 550 करोड़ रुपये
  रोजगार : 500
- **गोरखपुर रिसोर्सेज**
  सेक्टर : आयल उत्पाद
  निवेश : गोरखपुर में 35 करोड़ रुपये
  रोजगार : 150

	राशि	रोजगार
केआर पल्प पेपर्स (पेपर इंडस्ट्री) ■ शाहजहांपुर	502 करोड़	1000
इन्टेक्स मोबाइल (मोबाइल) ■ ग्रेटर नोएडा	500 करोड़	6000
एसीसी (सीमेंट) ■ धामपुर बिजनौर	500 करोड़	2700
ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज (लकड़ी उद्योग) ■ संडीला हरदोई	500 करोड़	800
पसवारा पेपर्स (पेपर इंडस्ट्री) ■ मेरठ	351 करोड़	200
मेट्रो कैश एंड कैरी (रिटेल चेन) ■ गाजियाबाद, वाराणसी, नोएडा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ	350 करोड़	2000
डीसीएम श्रीराम (एग्रो/फूड प्रोसेसिंग) ■ हरदोई	350 करोड़	642
निलया इन्फ्रा (रियल इस्टेट) ■ गाजियाबाद	350 करोड़	600
अंकुर उद्योग (स्टील प्लांट) ■ गोरखपुर	348 करोड़	600
केंट आरओ (आरओ मैन्युफैक्चरिंग) ■ नोएडा	300 करोड़	200
एसएससी बिल्डर्स (रियल इस्टेट) ■ गाजियाबाद	300 करोड़	200
केकेजी इंडस्ट्रीज (पंखा, कूलर उत्पादन) ■ नोएडा	250 करोड़	150
एम्पल्स इनर्जी (सोलर इनर्जी) ■ मिर्जापुर	250 करोड़	30
पीटीसी इंडस्ट्रीज (आईटी) ■ लखनऊ	205 करोड़	1100
त्रिवेनी इंजीनियरिंग (फूड/एग्रो प्रोसेसिंग) ■ बुलंदशहर	200 करोड़	200
अंबा शक्ति (स्टील प्लांट) ■ बुलंदशहर	183 करोड़	1000
निकिता पेपर्स (पेपर इंडस्ट्री) ■ शामली	182 करोड़	500
बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज (एग्रो/फूड प्रोसेसिंग) ■ बरेली	165 करोड़	320
बर्गर पेंट इंडिया (मैन्युफैक्चरिंग) ■ संडीला हरदोई	150 करोड़	400
खटटर एडिबिल्स (बिस्कुट) ■ कुशीनगर	150 करोड़	500
आईएल एंड एफएस इन्फ्रा (कचरा प्रबंधन) ■ कानपुर	150 करोड़	500
इंडोगल्फ इंडस्ट्रीज (विस्फोटक उत्पाद) ■ बबीना झांसी	131 करोड़	1000
धर्मपाल प्रेमचंद लि. (एग्रो/फूड प्रोसेसिंग) ■ नोएडा	120 करोड़	350
एसए आइरन एंड एलॉयज (आयरन प्लांट) ■ चंदौली	110 करोड़	50
गोल्डी मसाले (एग्रो/फूड प्रोसेसिंग) ■ कानपुर	100 करोड़	300
टिकौला सुगर मिल्स (पॉवर सेक्टर) ■ मुजफ्फरनगर	100 करोड़	530
श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स (मैन्युफैक्चरिंग) ■ गाजियाबाद	100 करोड़	200
राजेश मसाले (बिस्किट, डेयरी) ■ अमेठी	100 करोड़	75

रिलायंस जियो — सेक्टर : आईटी — ₹10,000 करोड़ का निवेश (पूरे प्रदेश में) — 2000 रोजगार

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर — इलेक्ट्रानिक मैन्यु — ₹10,000 करोड़ का निवेश (नोएडा) — 50,000 रोजगार

टेग्ना इलेक्ट्रानिक्स — इलेक्ट्रानिक्स — ₹5,000 करोड़ का निवेश (ग्रेटर नोएडा) — 30,000 रोजगार

इन्फोसिस — आईटी — ₹5,000 करोड़ का निवेश (नोएडा) — 14,000 रोजगार

पेटीएम — आईटी — ₹3,500 करोड़ का निवेश (गौतमबुद्ध नगर) — 14,000 रोजगार

बीएसएनएल — सेक्टर : आईटी — ₹5,000 करोड़ का निवेश (पूरे प्रदेश में) — --- रोजगार

अडानी पॉवर — पॉवर — ₹2,500 करोड़ का प्रथम चरण में निवेश (चंदनपुर, हापुड़) — 500 रोजगार

टीसीएस — आईटी — ₹2,300 करोड़ का निवेश (नोएडा) — 30,000 रोजगार

पतंजलि — फूड प्रोसेसिंग — ₹2,118 करोड़ का निवेश (ग्रेटर नोएडा) — 8,000 रोजगार

लूलू ग्रुप — रियल इस्टेट — ₹2,000 करोड़ का प्रथम चरण में निवेश (लखनऊ) — 10,000 रोजगार

यूपी बनेगा देश के विकास का इंजन

उत्तर प्रदेश, देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य सरकार ने नीतियों पर आधारित शासन पद्धति को अपनाते हुए 20 सेक्टोरल नीतियों को लागू किया है। श्रम कानूनों, करों, प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और अनुप्रयोगों को ई–सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश भूमि की उपलब्धता तथा आवंटन, करों के भुगतान, पारदर्शी एवं सहज रूप से उपलब्ध जानकारी, सिंगल विण्डो सिस्टम, पर्यावरण अनापत्ति हेतु पंजीकरण तथा सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु परमिट प्रदान करने वाले 05 प्रमुख राज्यों में से एक है। परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य सरकार दिन–रात यह सुनिश्चित कर रही है कि निवेशकर्ताओं को सभी सुविधाएं समयबद्धता के साथ उपलब्ध हो जाएं।

एम.ओ.यू. के 5 महीनों के अन्दर निवेश परियोजनाओं का शुभारम्भ, उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी' से प्रदेश की जनता के कल्याण के प्रति हमारी सरकार के समर्पण भाव का पता चलता है। यह यूपी के बदलते हुए औद्योगिक परिवेश का द्योतक है। राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों ने निवेशकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उनमें सकारात्मक भावनाओं को जागृत किया है।

प्रदेश में निवेश का नया वातावरण बना है। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, औद्योगिक सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शीघ्र ही देश के विकास का इंजन बनेगा।

–योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

बदला है प्रदेश का माहौल बढ़ा है निवेशकों का विश्वास

कुमार मंगलम बिड़ला
अध्यक्ष, आदित्य बिड़ला समूह

"हम अगले तीन वर्षों में यूपी में केमिकल और सीमेंट के क्षेत्र में 25,000 करोड़ रूपये का निवेश करेंगे। जल्द ही हमारा ग्रुप 7 हजार करोड़ रूपये की लागत से सीमेंट प्लांट लगाने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने समावेशी विकास की नई परिभाषा लिखी है। हम यूपी में लगातार निवेश करते रहेंगे।

गौतम अडानी
अध्यक्ष, अडानी ग्रुप

"हम यूपी में 36,500 करोड़ का निवेश करेंगे। इससे लगभग 1 लाख 90 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार ने 60 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जिस प्रकार से मात्र 5 महीनों में धरातल पर उतारा है, उससे उम्मीद है कि यूपी ट्रिलियन डालर इकोनॉमी वाला पहला राज्य बनेगा।

"हम 18 शहरों में इलेक्ट्रिक थ्री–व्हीलर्स उतारेंगे। इसमें 25000 ई–रिक्शा और लगभग इतने ही ऑटो रिक्शा होंगे। इस पर अगले चार वर्षों में कुल 1750 करोड़ रूपये का निवेश होगा और और एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने 9 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सुभाष चंद्रा
अध्यक्ष, एस्सेल समूह

"हमारा ग्रुप उत्तर भारत का सबसे बड़ा शापिंग मॉल लखनऊ में खोलेगा। यह शापिंग मॉल शहीद पथ पर सुशांत गोल्फ सिटी में लगभग दो हजार करोड़ रूपये की लागत से बनेगा। इससे 5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10 हजार लागों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी और नोएडा में भी लूलू के शापिंग माल खुलेंगे।

यूसुफ अली
चेयरमैन, लूलू ग्रुप

संजीव पुरी
प्रबंध निदेशक, आईटीसी लि.

"हमारी कंपनी 1000 करोड़ रूपये से लखनऊ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और गाजियाबाद में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करेगी। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसी यूपी को निवेश के लिए एक बेहतर स्थल बनाती हैं। हम यूपी में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करते रहेंगे।

बी आर शेट्टी
सीईओ, एनएमसी हेल्थकेयर

"हमारा ग्रुप हेल्थ केसर के क्षेत्र में वाराणसी में निवेश कर रहा है। जैसा माहौल यूपी में मिल रहा है, उससे बड़े पैमाने पर निवेशक आकर्षित हुए हैं। अब तत्काल लाइसेन्स मिल रहे हैं। अलग–अलग टेबल की जगह एक ही स्थान पर समाधान मिल रहा है। मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारी निवेशकों का सहयोग कर रहे है। ■

स्मार्ट सिटी मिशन से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर

स्मार्ट सिटी है एक मिशन

आजादी के बाद से शहरों को बेतरतीब और अव्यवस्थित तरीके से फैलने दिया गया, जिसका परिणाम हर शहरवासी भुगत रहा है। देश की जी.डी.पी. में शहरों की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अगर शहर अव्यवस्थित और अविकसित रहेंगे तो विकास बाधित होगा और ऐसी स्थिति में 21वीं सदी का भारत परिभाषित नहीं किया जा सकेगा। इसी सोच के तहत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित किया गया, जिन्हें 02 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करने की योजनाएं बनीं।

सरकार के लिए स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक मिशन है। यह मिशन है, देश को बदलने का। हमारे शहरों को न्यू इण्डिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का और 21वीं सदी के भारत में विश्वस्तरीय इंटेलीजेण्ट अर्बन सेण्टर्स खड़ा करने का।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह विचार लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी मिशन की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए आवास, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की 3397 करोड़ रुपए की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सरकार नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

विकास को नया आयाम

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इन योजनाओं की सफलता में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। 21 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में शहरों में निवास करती है। यहां पर सर्वाधिक 653 नगर निकाय हैं। विकास की नियोजित और व्यवस्थित सोच के तहत आम जनमानस को शहरों में लाभान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पिछले 16 महीनों से इन तीनों योजनाओं पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में 4 लाख 32 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दिए गए।

स्वच्छ भारत मिशन पर तेजी से कार्य हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण किया जा रहा है। दो अक्टूबर, 2018 तक सभी शहरों को ओ.डी.एफ. किए जाने की दिशा में कार्य हो रहा है। नगर निकाय आत्मनिर्भरता एवं आय में वृद्धि की दिशा में आगे बढ़े हैं। इनकी आय 18 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हुई है। गाजियाबाद और लखनऊ शहर म्युनिसिपल बॉण्ड के माध्यम से आने वाले समय में वैकल्पिक फण्डिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इनसे विकास को एक नया आयाम मिलेगा। ■

हमारी प्रतिबद्धता है कि भविष्य की व्यवस्थाओं का निर्माण '5 ई' पर आधारित हो। '5 ई' यानि ईज़ ऑफ लिविंग, एजुकेशन, इम्प्लॉयमेण्ट, इकोनॉमी और एण्टरटेनमेन्ट।

–प्रधानमंत्री

प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किए गए हैं, जिनके विकास का कार्य चल रहा है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ शहरों का नियोजित और व्यवस्थित विकास किया जा रहा है।

–मुख्यमंत्री

सवा साल में प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करने वाले पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगभग सवा साल के अपने अब तक के कार्यकाल में प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। दिनांक 19 मार्च, 2017 को जिलों के अपने दौरों की शुरूआत उन्होंने गोरखपुर से की थी।

उनका अपने गृह जिले गोरखपुर और वाराणसी में सर्वाधिक भ्रमण हुआ। इलाहाबाद और मथुरा भी वे पांच–पांच बार गए। सत्ता गवां देने का अंधविश्वास तोड़ते हुए वे तीन बार नोएडा भी गए। मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में दीपोत्सव मनाया तो मथुरा में रंगोत्सव। अब आगामी कुंभ की तैयारियां चल रही हैं।

अगस्त 2017 में बाढ़ के दौरान उन्होंने बलिया, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, और सीतापुर का न केवल दौरा किया, अपितु प्रभावित इलाकों में नागरिकों से मिलने नाव से भी गए। पीड़ितों को इससे पहले इतनी शीघ्र तथा पारदर्शी ढंग से राहत सामग्री का वितरण इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। जिले के हर दौरे में उन्होंने कानून–व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी की।

प्रदेश के सभी नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में बनें पार्क

देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं है। युद्धकाल के दौरान अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को विभिन्न प्रकार के वीरता पदक दिए जाते हैं। लेकिन शांतिकाल के दौरान भी आतंकवादी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं सहित कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें सैनिक अपनी कर्मठता, शौर्य, पराक्रम तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए देश सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में अपने उद्गार व्यक्त करतु हुए कहा कि हम सभी के लिए ये वीर सैनिक प्रेरक हैं, इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत माता की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारीजनों को राज्य सरकार हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के सभी नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्क बनाए जाने चाहिए। समाज, प्रदेश व देश की समृद्धि के लिए सभी को अहर्निश प्रयास करना चाहिए। तभी हम खुशहाल भारत बना सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर एक दिन में होगा 5 करोड़ वृक्षों का रोपण

वृक्षारोपण से ही हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। प्रकृति को संरक्षित करके बेहतर भविष्य की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाने में जनसहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। 'एक व्यक्ति–एक वृक्ष' के संकल्प को लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले 'वृहद वृक्षारोपण–2018' की समीक्षा अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि वनीकरण को आदर्श स्थिति में लाया जाए।

विशेष वृक्षारोपण अभियान में प्रदेश में रोपे जाएंगे 9.16 करोड़ पौधे

सरकार द्वारा इस वर्ष विशेष वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में कम से कम 9.16 करोड़ पौध रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण का यह लक्ष्य वन एवं वन्य जीव विभाग तथा 22 अन्य विभागों के लिए निर्धारित किया गया है।

15 अगस्त, 2018 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त विभागों द्वारा जन सहभागिता से वृक्षारोपण का अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। वन विभाग इस दिन, आवंटित कुल लक्ष्य का 30 प्रतिशत एवं अन्य विभाग आवंटित लक्ष्य का 80 प्रतिशत पौध रोपित करेंगे। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में पाँच करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे।

पॉलीथीन पर प्रतिबंध से बेहतर होगा पर्यावरण : सीएम

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता को अपनाकर हम स्वस्थ व समर्थ भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। इसके दृष्टिगत सरकार ने विगत 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन से कम के कैरी बैग को प्रतिबंधित कर दिया है और आगामी 02 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सभी प्रकार के डिस्पोज़ल आदि भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इन कार्यों से बेहतर पर्यावरण का निर्माण होगा, जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है।

शीरे के उत्पादन में 37.5 प्रतिशत की वृद्धि

जून 2018 तक 539.04 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन

प्रदेश में संचालित चीनी मिलों में सह–उत्पाद के रूप में माह जून 2018 तक शीरे के उत्पादन में गत वर्ष की अवधि के सापेक्ष 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 158 चीनी मिलें हैं। नवम्बर, 2017 से शुरू हुए पेराई सत्र में पेरे गये गन्ने से जून 2018 तक 539.04 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ।

विगत शीरा वर्ष 2016–17 की आलोच्य अवधि में कुल 392.04 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार माह जून–2018 तक शीरे के उत्पादन में गत वर्ष की अवधि के सापेक्ष 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ

पर्यावरण के दृष्टिगत और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है। इनसे प्रदूषण को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों के शुभारम्भ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारम्भ किया जा रहा है। इनमें से एक बस लखनऊ से कानपुर तथा दूसरी आगरा से दिल्ली के बीच चलायी जाएगी। आने वाले समय में इनकी सफलता को देखते हुए बड़े पैमाने पर इस प्रकार की बसें चलायी जाएंगी। इन बसों के संचालन से डीजल व पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और इस मद में बचत की जा सकेगी। यह बसें पर्यावरण हितैषी होने के साथ–साथ आवागमन का सहज और सस्ता साधन बनेंगी। इनसे जनता की सुविधा बढ़ेगी। ■

बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की पूरी है तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी और ऐसी स्थिति आने पर लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराते हुए बचाव कार्य किए जाएंगे। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मुहैया कराते हुए उनके लिए साफ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।

बाढ़ से निपटने के लिए जनपदों को मिले 380 करोड़ रूपये

राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए जनपदों को 380 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐसे में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी।

बाढ़ प्रभावित जिलों में कन्ट्रोल रूम

बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावित जनपदों में कन्ट्रोल रूम का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित करने के साथ–साथ बाढ़ चौकियां भी सक्रिय रहेंगी। बाढ़ग्रस्त जनपदों में नौकाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। यहां पर एन.डी.आर.एफ. तथा एस.डी.आर.एफ. की टीमें भी मौजूद रहेंगी।

प्रभावित परिवारों को 24 घंटे में मदद

प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुसार मात्र 24 घंटों के भीतर ही सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में भारी वर्षा के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जा रही हैं।

पुलिस करेगी तटबंधों की सुरक्षा में इंजीनियरों की सहायता

तटबंधों की सुरक्षा एवं बाढ़ नियंत्रण के कार्य में सिचाई विभाग के अभियन्ताओं को पुलिस की सहायता प्रदान की जाएगी। बाढ़ग्रस्त जनपदों के जिलाधिकारी तथा बाढ़ नियंत्रण तथा बचाव एवं राहत कार्यों में लगे कर्मी तैनाती स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

खाद्यान्न व चारे की भी व्यवस्था

बाढ़ग्रस्त जनपदों में केरोसीन, एल.पी.जी. सिलेण्डर, खाद्यान्न सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था होगी। जलभराव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद

प्रदेश में भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली से हुयी जन–धन की हानि हेतु राहत सहायता राशि के वितरण की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। अब तक मृतकों के परिजनों को 148 लाख, घायलों को लगभग 99 हजार, पशुहानि हेतु 02 लाख 91 हजार व क्षतिग्रस्त मकानों एवं झोपड़ियों हेतु लगभग 04 लाख 47 हजार रुपये राहत सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।

प्रदेश सरकार द्वारा आपदा पीड़ित मृतक परिजन को 4 लाख, घायल को 59100/- कच्चे-पक्के मकान की पूर्ण क्षति पर 95100/-,आंशिक क्षति में 5200/- तथा नष्ट झोपड़ी हेतु 4100/- रुपये राहत सहायता राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

31 जुलाई 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

लखीमपुर से दुधवा नेशनल पार्क तक बनेगा 10 मीटर चौड़ा मार्ग

खुली निविदा से 10 वर्षों के लिए होगा भदोही एक्सपोर्ट मार्ट के संचालक का चयन

प्राईवेट महाविद्यालयों का प्राचार्य बनना हुआ आसान

मुजफ्फरनगर में 12.419 हेक्टेयर में स्थापित होगा केवीके

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी